RNI NO. : 52419/91

# चाणक्य भूमि

हिन्दी दैनिक

• वर्ष : 32 • अंक : 19 • 02:02:2024 • शुक्रवार • मूल्य : 5/-

# न इनकम टैक्स में राहत न फसलों की एमएसपी बढ़ी

## मिडिल क्लास के लिए हाउसिंग स्कीम, रूफटॉप सोलर से 300 यूनिट तक फ्री बिजली

**नई दिल्ली (एजेंसी)।** बजट, बजट, बजट.. लो हो गया बजट पेश। लेकिन ये अंतरिम ही रहा। न टैक्स बदला, न बड़ी घोषणाएं। हालांकि सीतारमण 8 हफ्ते पहले ही बोल चुकी थीं कि साल चुनावी है, तो बजट अंतरिम ही रहेगा। यानी असली बजट जून-जुलाई में नई सरकार की वित्त मंत्री पेश करेंगी या करेगा। तब जो भी वित्त मंत्री बने। खैर, आते हैं आज के मसले पर। वित्त मंत्री करीब 58 मिनट बोलीं। इस दौरान सबसे ज्यादा 42 बार टैक्स और इतनी ही बार पीएम शब्द दोहराए। पर डायरेक्ट या इंडायरेक्ट, किसी भी तरह के टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया। हां पीएम से शुरू होने वाली योजनाएं खूब सारी गिनाई। इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं मिली। पुरानी टैक्स रिजीम पर 2.5 लाख रुपए तक की कमाई ही टैक्स फ्री रहेगी। हालांकि सेक्शन 87ए के तहत 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स बच सकता है। नई टैक्स रिजीम पर भी पहले की तरह 3 लाख रुपए तक की कमाई टैक्स फ्री है। इसमें 87ए के तहत सैलरीड पर्सन 7.5 लाख रुपए तक और बाकी 7 लाख तक की कमाई पर छूट ले सकते हैं।

**महिला: 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का टारगेट-** महिलाओं के लिए उम्मीद से कम घोषणाएं हैं। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सर्वाइकल कैंसर रोकने के लिए 9-14 साल की बच्चियों को फ्री टीका लगाया जाएगा। सभी आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं और हेल्पर्स को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाया जाएगा।

**किसान: फसलों की एमएसपी का दायरा नहीं बढ़ा-** फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस (एमएसपी) का दायरा नहीं बढ़ाया है। वहीं, साल में 6,000 रुपए की किसान सम्मान निधि में भी इजाफा नहीं किया गया है। सरकार ने एग्रीकल्चर सेक्टर को 1.27 लाख करोड़ दिए हैं, जो पिछली बार के मुकाबले केवल 2 फीसदी ही ज्यादा है। पिछली बार एग्रीकल्चर बजट में 1.25 लाख करोड़ मिले थे।

**शिक्षा-रोजगार: 1 लाख करोड़ का कॉर्पस फंड-** शिक्षा और रोजगार पर कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई। हालांकि 1 लाख करोड़ के कॉर्पस फंड का ऐलान किया है। इससे 50 साल तक की अवधि के लिए इंट्रेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा।

## उम्मीदों का बजट, पूरा है विश्वास...

### मिडल क्लास के लिए बजट में बड़ा ऐलान

नई दिल्ली (एजेंसी)। सरकार गरीबों के लिए पहले से ही पीएम आवास योजना के तहत मकान बना रही है। अब मिडल क्लास को भी बढ़ा तोहफा मिला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट स्पीच में कहा कि सरकार नई स्कीम का ऐलान करेगी। इस योजना के तहत मिडिल क्लास अपना घर बना या खरीद पाएगा। बता दें, पिछले साल पीएम मोदी ने लाल किले से अपने भाषण में मिडल क्लास के लिए इस योजना के लाने की बात कही थी।

उन्होंने अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा, हमारी सरकार मिडल क्लास के लिए नई योजना का ऐलान करेगी। इस स्कीम के तहत किराये के घर, झुग्गियों, अनधिकृत कालोनी और चाल में रहने वाले लोग अपना घर बना या खरीद पाएंगे।

## वित्त मंत्री ने 3 रेलवे कॉरीडोर बनाने का किया ऐलान, बढ़ेगी कनेक्टिविटी

बजट में वित्त मंत्री ने रेलवे सेक्टर के लिए भी कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने बताया कि 3 रेलवे इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोग्राम- एनर्जी, खनिज और सीमेंट शुरू करने का प्रस्ताव है। यह कॉरिडोर पीएम-गतिशक्ति स्कीम के तहत बनाए जाएंगे। इससे रेलवे नेटवर्क का विस्तार होगा तो कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। वित्त मंत्री

निर्मला सीतारमण ने कहा- मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी को सक्षम करने के लिए पीएम गति शक्ति के तहत परियोजनाओं की पहचान की गई है। इसके तहत लॉजिस्टिक्स स्किल में सुधार होगा तो लागत कम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा निर्मला सीतारमण ने 40,000 ट्रेन कोच को वंदे भारत कोच में अपग्रेड करने का भी ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2021 में मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गति शक्ति का ऐलान किया है।

## इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं, उतना ही देना पड़ेगा

मौजूदा सरकार के अंतिम बजट में इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के मोर्चे पर कोई राहत नहीं मिली है, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक ऐसी घोषणा की है जिससे करीब एक करोड़ इनकम टैक्सपेयर्स राहत की सांस ले सकते हैं। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में बकाया टैक्स को लेकर नोटिसों को निपटाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने का ऐलान किया है। 1962 से 2010 तक के 25 हजार रुपये तक की और वर्ष 2011 से 2015 तक के 10 हजार रुपये की बकाया टैक्स डिमांड को माफ किया जाएगा। अगर किसी के पास 1962 से लेकर वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान 25 हजार रुपये तक का डायरेक्ट टैक्स बकाए का नोटिस भेजा गया है तो ये मामले वापस ले लिए जाएंगे। इसी तरह वित्त वर्ष 2010-11 से 2014-15 के बीच बकाया डायरेक्ट टैक्स के नोटिस से जुड़े 10 हजार रुपये तक के मामलों को भी वापस लेने का फैसला किया गया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार के इस कदम से करीब एक करोड़ टैक्सपेयर्स को फायदा होगा।

## कांग्रेस ने मुंबई की तीन सीटों पर ठोका अपना दावा

### शिवसेना केवल एक देने को तैयार, इंडिया में तकरार

मुंबई (एजेंसी)। इंडिया गठबंधन के लिए सीट शेयरिंग बड़ी चुनौती बनती जा रही है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने एक भी सीट देने से इनकार कर दिया है। वहीं, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने भी अकेले लड़ने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र में भी बंटवारे की राह आसान नहीं दिख रही है। कांग्रेस ने मुंबई की कुल छह सीटों में से तीन पर दावा ठोक दिया है। इसके कारण महा

विकास अघाड़ी में शामिल एनसीपी और शिवसेना (उद्धव) के बीच आम सहमति नहीं बन पा रही है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना कांग्रेस के दावे को सिरे से खारिज कर दिया और केवल एक सीट देने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि हाल ही में कांग्रेस के दिग्गज नेता मिलिंद देवड़ा ने इसी मुद्दे पर पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि, कांग्रेस के एक शीर्ष नेता का कहना है कि 38 सीटों पर सहमति बन गई है। उन्हें इस बात की उम्मीद है कि 2 फरवरी को एमवीए की अगली बैठक में शेष सीटों पर अधिकांश विवादों का समाधान हो जाएगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर कोई फैसला नहीं होता है तो एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, यूबीटी सेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और एआईसीसी पर्यवेक्षक रमेश चेन्निथला सीट बंटवारे को लेकर विवाद सुलझाएंगे।

## कमाई कम और खर्च ज्यादा, कांग्रेस का बिगड़ा बजट

- **भारत जोड़ो यात्रा पर ही खर्च हुआ 30 पर्सेंट बजट, फंडिंग में बड़ी गिरावट**

**नई दिल्ली (एजेंसी)।** सितम्बर 2022 से जनवरी 2023 के बीच कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर की राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर कांग्रेस ने कुल 71.8 करोड़ रुपये खर्च किए थे, जो उसके सालाना खर्च का 15.3 फीसदी है। यह रकम 2022-23 के दौरान पार्टी के प्रशासनिक और सामान्य खर्चे का कुल 30 फीसदी से ज्यादा है। चुनाव आयोग के पास दाखिल पार्टी की नवीनतम वार्षिक

ऑडिट रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022-23 में कांग्रेस की कुल आमदनी वित्त वर्ष 2021-22 में 541 करोड़ रुपये से गिरकर 452 करोड़ रुपये पर पहुंच गई जबकि इसी अवधि में इसका खर्च 400 करोड़ रुपये से बढ़कर 467 करोड़ रुपये हो गया। चुनाव आयोग द्वारा बुधवार को सार्वजनिक की गई पार्टी की ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, 2021-22 में चुनावी बांड के माध्यम से कांग्रेस की कुल प्राप्तियां 236 करोड़ रुपये थी, जो 2022-23 में घटकर 171 करोड़ रुपये रह गई हैं।

## संगरूर सांसद की हुई गिरफ्तारी, पंजाब में बवाल

- **सिमरनजीत सिंह मान को पुलिस ने किया हाउस अरेस्ट**

### कई कार्यकर्ता हिरासत में

**चंडीगढ़ (एजेंसी)।** शिरोमणि अकाली दल सांसद सिमरनजीत सिंह मान को उनके घर तलानिया से हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। सिमरनजीत सिंह संगरूर से सांसद हैं। साथ ही उनके कई पार्टी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पार्टी कार्यकर्ताओं के अनुसार, मान को उनके संगरूर स्थित घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी गई और खबर लिखे जाने तक उन्हें कथित तौर पर घर में नजरबंद रखा गया। बताया जा रहा है कि शिरोमणि अकाली अमृतसर की ओर से आज भाना के समर्थन में धरना देने वाले थे। सिमरनजीत सिंह मान ने 1 फरवरी को पंजाब से दिल्ली तक लंबी दूरी की ट्रेनों के लिए प्रमुख क्रॉसिंग धूरी 'दोहला रेल क्रॉसिंग' पर रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया था, जिसके कारण बड़ी संख्या में ट्रेनें प्रभावित होतीं। हालांकि, 'रेल रोको' विरोध सफल नहीं हो सका, क्योंकि पुलिस ने संगरूर, बरनाला, मालेरकोटला, मनसा और अन्य स्थानों से कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया।

### डिफेंस

## पिछले साल के मुकाबले 3.4 फीसदी की बढ़ोतरी

डिफेंस खर्च के लिए 6.2 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। यह पिछले साल से केवल 0.27 लाख करोड़ यानी 3.4 फीसदी ज्यादा है। हालांकि अंतरिम बजट में सबसे बड़ा हिस्सा डिफेंस का ही है। इसे कुल बजट का 8 फीसदी मिला है। सरकार डीप-टेक टेक्नोलॉजी को मजबूत करेगी, ताकि देश हथियारों के लिए आत्मनिर्भर बने। मेट्रो और नमो भारत जैसे प्रोजेक्ट्स बढ़ाए जाएंगे। देश में रेलवे फ्रेट कॉरिडोर के अलावा 3 और रेलवे कॉरिडोर बनाए जाएंगे। साथ ही 40 हजार रेल कोचेस को वंदे भारत स्टैंडर्ड का बनाया जाएगा।

# पीएम मोदी की बताई 4 जातियों पर फोकस

जातीय राजनीति पर चोट करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों अपने ही तरीके से देश में 4 जातियां होने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि देश में सिर्फ 4 ही जातियां हैं और उनके कल्याण से ही भारत विकसित हो जाएगा। पीएम मोदी ने इन 4 जातियों में गरीब, किसान, महिला और युवा को गिनाया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब गुरुवार को अंतरिम बजट पेश कर रही थीं तो उन्होंने भी इन चार जातियों पर पूरा फोकस रखा। अंतरिम बजट में निर्मला सीतारमण ने बताया कि बीते 10 सालों में इन लोगों के लिए क्या काम हुआ है और आगे क्या प्रावधान किए गए हैं। वित्त मंत्रालय की ओर से दी गई बजट कॉपी में सबसे पहले गरीब कल्याण की बात कही गई है। जिसमें बताया गया है कि कैसे सरकार ने डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर के जरिए 2.7 लाख करोड़ रुपये बचा लिए और गरीबों को सीधे बिना किसी सेंधन के पूरी रकम मिल गई। इसके अलावा 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने और पीएम स्वनिधि योजना के जरिए 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को लोन देने की बात कही गई है। यही नहीं विश्वकर्मा योजना को भी सरकार ने गिनाया है कि कैसे कारीगर जातियों को इससे फायदा मिल रहा है। युवाओं की बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद भी बजट की तारीफ करते हुए 1 लाख करोड़ रुपये के उस फंड की बात की है, जिसमें रिसर्च और इनोवेशन का प्रावधान है।

# कुछ नियम बना दो मीलॉर्ड, ऐसे कैसे अरेस्ट हो सकता है सीएम

## सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हेमंत सोरेन, कहा-मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट को लेकर कुछ नियम तय हों

**रांची (एजेंसी)।** झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी की ओर से गिरफ्तार किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने ईडी की ओर से खुद को गिरफ्तार किए जाने को चुनौती दी है। उनकी ओर से पक्ष रखते हुए सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने अदालत से गुहार लगाई कि मनी लॉन्ड्रिंग के सेक्शन 19 के प्रावधानों को आपको तय करना होगा। उन्होंने कहा कि आखिर किसी को इस तरह कैसे अरेस्ट किया जा सकता है। उन्होंने बेंच से अपील की कि आप जल्दी ही इस पर फैसला लीजिए। इस पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कल ही सुनवाई करने पर सहमति जताई। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। इस पर कपिल सिब्बल ने बताया कि हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट से अपनी अर्जी को वापस ले लिया है। कपिल सिब्बल ने इस दौरान हेमंत सोरेन की

गिरफ्तारी के तरीके पर भी सवाल उठाया। उन्होंने अदालत में कहा कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के मेमो में टाइम10 बजे का बताया गया है, जबकि वास्तव में अरेस्ट 5 बजे शाम को किया गया। यह बेहद गंभीर मामला है। इस पर आपको ध्यान देना चाहिए और राहत देनी चाहिए। इस पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि हेमंत सोरेन के खिलाफ आरोप बेहद गंभीर हैं। यह भी ध्यान देने की बात है। यही नहीं सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने गिरफ्तारी को राजनीतिक कारणों से भी जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि आखिर चुनावों से पहले ही क्यों गिरफ्तारियां तेज हो जाती हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आपके सभी सवालों पर कल विचार करेंगे। गौरतलब है कि गिरफ्तारी के चलते हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री पद से ही इस्तीफा दे दिया है और अब उनकी जगह सीनियर नेता चंपई सोरेन राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे।

# मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत

### ज्ञानवापी केस

- **ज्ञानवापी में पूजा के आदेश के खिलाफ तत्काल सुनवाई से इनकार**

**नई दिल्ली (एजेंसी)।** वाराणसी जिला अदालत के आदेश के खिलाफ शीर्ष न्यायालय पहुंची ज्ञानवापी मस्जिद समिति को कोर्ट से झटका लगा है। शीर्ष न्यायालय ने मामले में तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। बुधवार को ही वाराणसी की कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में व्यासजी के तहखाने में पूजा के अधिकार के निर्देश दिए थे। अदालत की तरफ से बताए गए स्थान पर देर रात पूजा-अर्चना का दौर भी शुरू हो गया है। बुधवार को ही अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद की तरफ से जिला अदालत के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दाखिल कर दिया था। इधर, समिति के वकील बुधवार रात तत्काल सुनवाई की मांग लेकर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार के आवास पर भी पहुंच गए थे। उन्होंने आशंका जताई थी कि रात में मंदिर में पूजा की जाएगी। रजिस्ट्रार की तरफ से बताया गया कि वह निर्देश लेने के बाद आगे की जानकारी देंगे। खबर है कि अल सुबह ही रजिस्ट्रार ने मस्जिद समिति

के वकील फुजैल अहमद अय्यूबी से बात की थी। इस दौरान उन्होंने मिले निर्देशों को बताया और कहा कि उन्हें इलाहबाद हाईकोर्ट जाना होगा। आवेदन में मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा गया था कि वाराणसी कोर्ट के आदेश के बाद से ही प्रशासन रात में पूजा के लिए जल्दबादी में काम कर रहा है। हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने एक दिन पहले ही पीटीआई-भाषा से बातचीत में इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि जिला न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने तहखाने में पूजा पाठ करने का अधिकार व्यास जी के नाती शैलेन्द्र पाठक को दे दिया है। मुस्लिम पक्ष ने इस आदेश को अदालत में चुनौती देने का फैसला किया है। यादव ने बताया कि जिला न्यायाधीश ने अपने आदेश में मूर्तियों की पूजा सात दिन के भीतर कराने के निर्देश दिए।

# पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून की तैयारी

### 'मुन्ना भाई' की खैर नहीं, 1 करोड़ लगेगा जुर्माना

**नई दिल्ली (एजेंसी)।** परीक्षाओं में धांधली रोकने और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। खबर है कि सोमवार को संसद में इससे जुड़ा विधेयक भी पेश हो सकता है। खास बात है कि बजट सत्र के शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अभिभाषण में पेपर लीक के खिलाफ कानून का जिक्र किया था। खबर है कि इसमें 10 साल की जेल और एक करोड़ रुपये जुर्माने जैसे कड़े प्रावधान शामिल हैं। सरकारी नौकरियों और केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षाओं में गलत संसाधनों के इस्तेमाल के खिलाफ नए विधेयक की तैयारी है। रिपोर्ट के अनुसार, इस प्रस्तावित कानून का मकसद माफिया समेत ऐसे संस्थानों और लोगों पर नकेल कसना है, जो पेपर लीक, किसी और से परीक्षा दिलाने, कंप्यूटर हैकिंग में शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार, तय अभ्यर्थी के स्थान पर किसी और को परीक्षा

दिलाने, पेपर सॉल्व कराने, केंद्र के अलावा कहीं और परीक्षा आयोजित करने या परीक्षा से जुड़ी धोखेबाजी की जानकारी नहीं देने वालों को 3 से 5 सालों की सजा हो सकती है। साथ ही 10 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है। कहा जा रहा है कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा करा रहा सर्विस प्रोवाइडर अगर गलत कामों में शामिल पकड़ा जाता है, तो 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लग सकता है। साथ ही उस पर 4 सालों के लिए परीक्षा आयोजित कराने पर भी रोक लग सकती है।

### इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं

**3 लाख तक की इनकम ही रहेगी टैक्स फ्री, लेकिन 87ए के तहत 7.5 लाख रुपए तक टैक्स छूट**

सरकार ने अंतरिम बजट में आम आदमी को इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं दी है। पुरानी टैक्स रिजीम चुनने पर अभी भी आपकी 2.5 लाख रुपए तक की इनकम ही टैक्स फ्री रहेगी। हालांकि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87 के तहत आप 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स बचा सकते हैं।

वहीं नई टैक्स रिजीम चुनने पर पहले की तरह ही 3 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स नहीं देना होगा। इसमें भी इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87 ए के तहत सैलरीड पर्सन 7.5 लाख रुपए तक की इनकम पर और अन्य लोग 7 लाख तक की इनकम पर टैक्स छूट पा सकते हैं।

### टैक्स छूट

सीए कार्तिक गुप्ता के अनुसार इस बार टैक्स के पुराने पेंडिंग मामलों को लेकर राहत दी गई है। इसके तहत 1962 से वित्त वर्ष 2009-10 तक के पेंडिंग डायरेक्ट टैक्स के मामलों में टैक्स माफ कर दिया जाएगा। हालांकि ये तभी होगा जब आप पर 25000 रुपए तक का टैक्स बन रहा हो।

### टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं

● डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। ● रक्षा खर्च में 11.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी, अब यह जीडीपी का 3.4 प्रतिशत होगा। ● आशा बहनों को भी आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाएगा। ● तिलहन के अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी।

## बजट एक तरह से यह 'स्वीट स्पॉट' है: पीएम मोदी

● बजट में युवा भारत की आकांक्षाओं की झलक, विकसित राष्ट्र बनाने की गारंटी

**नईदिल्ली (एजेंसी)।** नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बजट में राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखते हुए पूंजीगत व्यय को 11,11,111 करोड़ रुपये की ऐतिहासिक ऊंचाई दी गई है। उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्रियों की भाषा में कहें तो एक तरह से यह 'स्वीट स्पॉट' है। अंतरिम बजट समावेशी और नवोन्वेषी बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसमें निरंतरता का भरोसा है। यह विकसित भारत के सभी 4 स्तंभों- युवा, गरीब, महिला और किसान को सशक्त बनाएगा। यह बजट 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की गारंटी देता है। उन्होंने कहा कि इस बजट में युवा

भारत की युवा आकांक्षाओं की झलक है। बजट में दो अहम फैसले किये गये। रिसर्च और इनोवेशन के लिए 1 लाख करोड़ रुपये के फंड का ऐलान किया गया है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बजट में राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखते हुए पूंजीगत व्यय को 11,11,111 करोड़ रुपये की ऐतिहासिक ऊंचाई दी गई है। उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्रियों की भाषा में कहें तो एक तरह से यह 'स्वीट स्पॉट' है। इससे भारत का 21वीं सदी का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होने के साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के असंख्य नए अवसर तैयार होंगे। उन्होंने कहा कि यह बजट गरीबों और मध्यम वर्ग के सशक्तिकरण और उनके लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर जोर देता है। गरीबों के लिए 2 करोड़ और घर बनाने का ऐलान किया गया है. हमारा लक्ष्य अब 3 करोड़ 'लखपति दीदी' बनाने का है। आशा और आगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा। मोदी ने कहा कि आयकर छूट योजना से मध्यम वर्ग के 1 करोड़ लोगों को राहत मिलेगी। इस बजट में किसानों के लिए अहम फैसले लिए गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्रीय बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करने का रोडमैप तैयार करता है।

### निर्मला सीतारमण ने पेश किया अंतरिम बजट

# टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं

# विकास पर फोकस

### गरीब, महिला, युवा, किसान इन 4 पर खास ध्यान

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मौजूदा सरकार का आखिरी बजट पेश किया। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये अंतरिम बजट है। इस दौरान वित्त मंत्री का बजट भाषण करीब एक घंटे चला। मोदी 2.0 सरकार के इस अंतरिम बजट में करदाताओं को खुश होने के लिए बहुत कुछ नहीं मिला। सरकार पूंजीगत व्यय और अन्य सामाजिक कल्याण सेवाओं में निरंतर रुचि के साथ राजकोषीय कंसोलिडेशन के मार्ग पर आगे बढ़ती नजर आई है। जिस तरह से पीएम मोदी किसानों, युवाओं, महिलाओं, गरीबों पर खास फोकस की बात करते हैं। निर्मला सीतारमण ने भी एक बार फिर अलग-अलग वर्ग के समर्थन में आवाज बुलंद की। वित्त मंत्री ने अपना बजट भाषण शुरू करने से पहले ही साफ कर दिया कि उनका पूरा फोकस देश के विकास पर केंद्रित रहेगा। बजट रखने पहले पहले निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगले पांच साल बेहद अहम हैं, ये अभूतपूर्व विकास और 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के सुनहरे पल होंगे। जानिए बजट की मुख्य बातें-

**राजकोषीय घाटे को कम करने पर ध्यान-** फिस्कल फ्रूडेंस के रास्ते पर चलते हुए, सरकार की ओर से बार-बार कहा गया कि वह वित्त वर्ष 2026 तक राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 4.5 फीसदी तक कम करना चाहती है। अंतरिम बजट के दौरान, फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण ने राजकोषीय घाटे को लेकर बड़ी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सकल घरेलू उत्पाद के 5.9 फीसदी के पिछले लक्ष्य से घटाकर सकल घरेलू उत्पाद का 5.8 प्रतिशत कर दिया है। वहीं वित्त वर्ष 2025 के लिए ये लक्ष्य जीडीपी का 5.1 फीसदी निर्धारित किया गया है। फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए शुद्ध उधारी 11.75 लाख करोड़ रुपये देखने को मिली है जबकि केंद्र की सकल उधारी 14.13 लाख करोड़ रुपये देखी गई है। सरकार ने वित्त वर्ष 2025 के लिए रक्षा क्षेत्र में आवंटन को 4 फीसदी बढ़ाकर 6.2 लाख करोड़ रुपये कर दिया है। ये वित्त वर्ष 2024 के बजटीय अनुमान 5.94 लाख करोड़ रुपये से अधिक है।

**टैक्स को लेकर हुआ ये ऐलान-** वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि टैक्स ढांचे में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, चाहे वह प्रत्यक्ष कर हो या अप्रत्यक्ष। हालांकि, सॉवरेन वेल्थ फंड और पेंशन फंड में किए गए निवेश को एक और साल के लिए टैक्स फ्री कर दिया गया है। वित्त वर्ष 2025 में कुल राजस्व प्राप्ति अब 30 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया जा रहा है, जो वित्त वर्ष 2024 में 26.99 लाख करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से अधिक है।

**इन्फ्रास्ट्रक्चर पर जोर-** वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि वित्त वर्ष 2025 के लिए पूंजीगत व्यय परिव्यय का बजट 11 फीसदी बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपये या जीडीपी का 3.4 फीसदी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले चार साल में पूंजीगत व्यय तीन गुना होने से आर्थिक विकास और रोजगार सृजन पर कई गुना प्रभाव पड़ा है। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा बढ़ाने के लिए लगभग 40,000 सामान्य रेल बोगियों को वंदे भारत मानकों में परिवर्तित किया जाएगा। इसके अलावा, तीन प्रमुख आर्थिक रेलवे कॉरीडोर यानी ऊर्जा, खनिज, और सीमेंट कॉरीडोर तैयार किए जाएंगे। इसके साथ ही पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरीडोर और हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरीडोर्स लागू किए जाएंगे।

### नारी शक्ति

सरकार ने महिला उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण उपलब्ध कराए हैं। एसटीईएम पाठ्यक्रमों में अब 43 फीसदी नामांकन लड़कियों और महिलाओं का है। ये दुनिया में सबसे ज्यादा है। वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम आवास योजना के तहत 70 फीसदी से अधिक घर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को दिए गए हैं। सरकार लड़कियों (9-14 वर्ष) के लिए सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण को प्रोत्साहित करेगी। बेहतर पोषण वितरण के लिए सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 में तेजी लाई जाएगी।

## अब हर आदमी के पास होगा अपना मकान

फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने आज वित्त वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट में मिडिल क्लास के लिए कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि सरकार मिडिल क्लास के लिए एक खास योजना शुरू करेगी। इससे किराए के मकानों या झुग्गी-झोपड़ी, चॉल और अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले मध्यम वर्ग के लोगों को अपना मकान खरीदने या बनाने में मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग के लिए सरकार नई योजना बनाएगी। इससे किराए के मकानों या झुग्गी-झोपड़ी, चॉल और अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले मध्यम वर्ग के लोगों को अपना मकान खरीदने या बनाने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्री ने साथ ही मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए रूफटॉप सोलर एनर्जी को लेकर भी बड़ी घोषणा की। सर्वोदय इससे मध्यम वर्ग को हर साल बिजली में खर्च होने वाली बड़ी राशि बचाने में मदद मिलेगी। सरकार ने साथ ही पीएम-आवास के लिए भी आवंटन बढ़ा दिया है। आइए जानते हैं कि सरकार के इन उपायों का क्या फायदा होगा।

### युवाओं के लिए किए ये ऐलान

साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि देश में 3 हजार नए आईटीआईआई खोले गए। इसका फायदा युवाओं को मिला है। देश में 1.40 करोड़ युवाओं को स्किल इंडिया की ट्रेनिंग दी गई है। वहीं 15 नए AIIMS और 390 नए विश्वविद्यालय बनाए गए हैं। बताया कि देश की समृद्धि युवाओं को पर्याप्त रूप से साधन संपन्न करने और बनाने पर निर्भर करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 से परिवर्तनकारी सुधार लाए जा रहे हैं। बच्चों का समग्र और चहुंमुखी विकास किया जा रहा है।

## पिछले 10 साल में सरकार ने महिला कल्याण की दिशा में अहम काम वित्त मंत्री निर्मला

वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट में महिलाओं और लड़कियों के लिए खास जिक्र किया। अपने भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले 10 साल में सरकार ने महिला कल्याण की दिशा में अहम काम किया है। वित्तमंत्री ने कहा कि तीन तलाक को अवैध बनाना, महिलाओं के लिए एक तिहाई विधायी सीटें आरक्षित करना सरकार के महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम पर प्रकाश डालता है। इसके अलावा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार की तरफ से अनेक कदम उठाए गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि महिलाओं की उद्यमशीलता 28 फीसदी बढ़ी है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में पीएम मुद्रा योजना के तहत 30 करोड़ कर्ज महिला उद्यमियों को बांटे गए हैं।

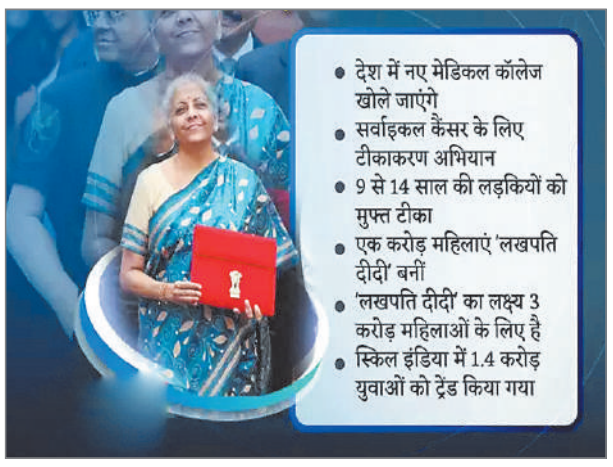


### सर्वाइकल कैंसर रोकने को टीकाकरण अभियान

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार की सर्वाइकल कैंसर रोकने की योजना है। सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए लिए खास टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। इसमें 9 से 14 साल की सभी लड़कियों का टीकाकरण किया जाएगा।

### 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं

लखपति दीदी पर बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि 83 लाख स्वयं सहायता समूह 9 करोड़ महिलाएं जुड़कर सामाजिक परिवेश को बदल रही हैं। इससे महिलाओं के जीवन में बदलाव हुआ है। वित्त मंत्री ने कहा कि अब तक करीब 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। वे लोगों के लिए प्रेरणा बन रही हैं। उन्होंने कहा कि हमने लखपति दीदी को 2 करोड़ से बढ़ाकर तीन करोड़ करने का लक्ष्य रखा है। उद्यमिता, सुगम्य जीवन और महिलाओं के लिए सम्मान के माध्यम से उनके सशक्तिकरण को इन 10 वर्षों में गति मिली है। 10 साल में उच्चतर शिक्षा में महिलाओं का नामांकन 28 प्रतिशत बढ़ गया है।

### ऑटो-सेक्टर को लेकर बड़ा ऐलान

## ग्रीन मोबेलिटी को बढ़ावा देने पर दिया जोर

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अंतरिम बजट पेश कर दिया है। इस बजट में कई बड़े ऐलान किए गए हैं। जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर बेहतर इको सिस्टम डेवलप करने की बात कही गई है। चलिए जानते हैं ऑटो-सेक्टर को क्या मिला।

वित्त मंत्री ने कहा- भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ रही है। साथ ही हमारी सरकार का लक्ष्य ग्रीन मोबेलिटी को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल नीतियों को जारी रखना है। ईवी मैन्युफैक्चरिंग और चार्जिंग इको सिस्टम के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा दिया जाएगा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री सबसे ज्यादा होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार इसको लगातार प्रोत्साहित कर रही है। इलेक्ट्रिक वाहन कम प्रदूषण फैलाते हैं। इसके अलावा उन्होंने हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए एक नई बायो मैन्युफैक्चरिंग स्कीम की शुरुआत की भी बात कही है।

उन्होंने आगे कहा- देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए क्रेंद्र सरकार चार्जिंग स्टेशन के इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए नए ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगी। इसके अलावा मौजूदा वेंडर्स के साथ-साथ ही नए उद्यमियों को भी शामिल किया जाएगा। इस चार्जिंग निर्माण के लिए युवाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। इसके लिए उन्हें तकनीकी ट्रेनिंग दी जाएगी। इससे युवाओं को ईवी चार्जिंग सेक्टर में रोजगार देने के लिए उनको पर्याप्त मौके दिए जाएंगे।

इसके अलावा वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने देशभर के सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक वाहनों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार सार्वजनिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक बसों को सार्वजनिक परिवहन के रुप में इस्तेमाल करने के लिए चरणबद्ध तरीके से काम कर रही है। देश में ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए और पर्यावरण को स्वस्थ बनाने और देश में पेट्रोल डीजल पर निर्भरता को कम किया जा रहा है। सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल के अलावा सरकार निजी क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा दे रही हैं।

## सालभर में होगी 18,000 रुपये की बचत, जानिए क्या है योजना और किस-किसको होगा फायदा

फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 का अंतरिम बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत एक करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। दावा किया जा रहा है कि इससे उपभोक्ताओं को हर साल 15,000 से 18,000 रुपये की बचत होगी। इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी, 2024 को की थी। इसके तहत गरीब या मध्य वर्ग के लोगों के छत पर सोलर पैनल लगाया जाएगा। इससे लोगों को बिजली के भारी बिलों से छुटकारा मिलेगा। साथ ही वे फालतू बिजली को बेच भी सकते हैं। इस योजना के तहत साल 2026 तक 40 हजार मेगावाट बिजली बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को लॉन्च करने हुए कहा था कि इसे सफल बनाने के लिए एक बड़ा राष्ट्रीय अभियान चलाने की जरूरत है। सरकार ने साल 2014 में सौभाग्य योजना की शुरुआत की थी। इसमें घरों की छत पर सोलर पैनल लगाकर साल 2022 तक 40,000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर 2023 तक इस योजना से महज 11,000 मेगावाट बिजली का ही उत्पादन हो पाया। अब इस योजना को गति देने के लिए ही पीएम सर्वोदय योजना का शुभारंभ किया गया है।

# आइपीएस अधिकारियों ने जारी किया संपत्ति का ब्योरा

# डीजीपी ने बेटे को पढ़ाने के लिए घर को गिरवी रखकर लिया है लोन

**पटना, एजेंसी।** बिहार के आइपीएस अधिकारियों ने बुधवार को अपनी-अपनी अचल संपत्ति का विवरण जारी किया है. इसके अनुसार डीजीपी आरएस भट्टी के पास चंडीगढ़ में पुश्तैनी जमीन और आवासीय घर है. पुश्तैनी जमीन में आधी हिस्सेदारी है, जिसकी कीमत एक करोड़ 80 लाख है. वहीं 500 वर्ग यार्ड के आवासीय परिसर में उनकी आधी हिस्सेदारी एक करोड़ 86 लाख रुपये की है. डीजीपी ने इस घर को बैंक में गिरवी रखकर बेटे के लिए शिक्षा ऋण लिया है.

### निगरानी के डीजी आलोक राज की संपत्ति

निगरानी के डीजी आलोक राज के पास मुजफ्फरपुर के सरैया में 66 डिसमिल, 33 डिसमिल एवं 47 डिसमिल पुश्तैनी जमीन है, जिस पर भाई-बहनों की भी हिस्सेदारी है. पटना के कंकड़बाग में 3800 वर्गफीट में आवास है, जिसकी वर्तमान कीमत 3.5 करोड़ है. इसमें भी भाई-बहनों की भी हिस्सेदारी है. उत्तर प्रदेश के नोएडा में 1850 वर्गफीट का फ्लैट है. उसकी कीमत 89 लाख रुपये है. इस पर पत्नी के साथ संयुक्त मालिकाना हक है.

### आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी की संपत्ति

आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी नैय्यर हसनैन खान की लखनऊ में पत्नी के नाम पर 315 वर्गमीटर में डुप्लेक्स है, जिसका निर्माण कर्ज लेकर किया गया है. पटना सिटी में 855 वर्गफीट व्यावसायिक जमीन पिता से उपहार में मिली है. यूपी के नोएडा में पत्नी के नाम पर फ्लैट है. यह होम लोन लेकर खरीदी गई है.

### एडीजी कुंदन कृष्णन के पास कितनी संपत्ति..

एडीजी कुंदन कृष्णन के पास बिहार के नालंदा में सात एकड़, पांच एकड़ और आधा एकड़ पुश्तैनी जमीन है. पटना के लंगरटोली में दो कट्ठे में आवासीय पुश्तैनी मकान, राजेंद्रनगर में तीन करोड़ रुपये का छह कट्ठे में बना

### पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार की संपत्ति

पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार के पास यूपी के लखनऊ में पिता से मिली 240 वर्गमीटर पुश्तैनी जमीन है. हरियाणा के फरीदाबाद में पत्नी के साथ संयुक्त रूप से लिया गया 1575 वर्गफीट का निर्माणाधीन फ्लैट है. पंजाब के लुधियाना में रिश्तेदारों से कर्ज लेकर 400 वर्ग यार्ड जमीन भी है.

आवास और हरियाणा के गुरुग्राम में पत्नी के नाम पर संयुक्त रूप से लिया गया फ्लैट है जिसकी कीमत एक करोड़ 17 लाख रुपये है. नालंदा के दरियापुर में 3.8 एकड़ में अपने नाम पर ली गई कृषि भूमि भी है.

### अग्निशमन व होमगार्ड की डीजी शोभा ओहटकर की संपत्ति

अग्निशमन व होमगार्ड की डीजी शोभा ओहटकर के पास पटना के आशियाना नगर में पिता से उपहार मे मिला फ्लैट है, जिसकी वर्तमान कीमत करीब 25 लाख आंकी गयी है. महाराष्ट्र के पुणे में करीब दो हजार वर्गफीट में घर है. उसकी अनुमानित कीमत एक करोड 75 लाख है. इस संपत्ति से 3.60 लाख रुपये की वार्षिक आय होती है.

## समस्तीपुर समेत बिहार के अन्य जिलों में दो दिन बारिश का अलर्ट

**समस्तीपुर, एजेंसी।** बिहार में लोगों को ठंड से हल्की राहत मिली है। मगर अधिकतर जगहों पर गुरुवार से आंशिक बादल छाए रहने के आसार हैं। तीन दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में गिरावट और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। यानी कि लोगों को दो तरह का मौसम परेशान करने वाला है। साथ ही 2 से 3 फरवरी के बीच प्रदेश के कुछ शहरों में बूंदाबांदी होने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी बिहार में एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। इसके प्रभाव से बादल छाए रहने और बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। वहीं 3 फरवरी को एक और पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है। इसके 5 फरवरी तक जाने के आसार हैं। इसके बाद एक बार फिर से राज्य में ठंड बढ़ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को प्रदेश के जीरादेई, बक्सर, डेहरी, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई का न्यूनतम पारा गिरा। वहीं 24 शहरों के तापमान में बढ़ोतरी हुई। पटना सहित प्रदेश के 26 शहरों के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं कैमूर, नवादा, जमुई, फारबिसगंज, मधुबनी में गिरावट आई है। प्रदेश का सबसे ठंडा शहर 5.2 डिग्री के साथ मोतिहारी और सबसे गर्म 26 डिग्री सेल्सियस के साथ खगड़िया रहा।

# प्रदेश में नीतीश कुमार, राबड़ी देवी, शाहनवाज सहित एमएलसी की 11 सीटें होंगी खाली

**पटना, एजेंसी।** बिहार विधानसभा में निर्वाचित 11 सदस्यों का कार्यकाल मई के पहले सप्ताह में पूरा हो रहा है. विधान परिषद की रिक्त होनेवाली इन सीटों पर चुनाव का कार्यक्रम जल्द ही जारी होगा. विधान परिषद के जिन सदस्यों का कार्यकाल पूरा होनेवाला है उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन, जदयू नेता व पूर्व मंत्री संजय कुमार झा, कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा, हम नेता संतोष कुमार सुमन, भाजपा नेता मंगल पांडेय, राजद नेता रामचंद्र पूर्वे, जदयू नेता खालिद अनवर व रामेश्वर महतो और भाजपा नेता संजय पासवान शामिल हैं.

### एनडीए के पांच उम्मीदवार का जीतना तय माना जा रहा

बिहार की राजनीति के नये समीकरण में विधानसभा की संख्या बल के आधार पर एनडीए के पांच उम्मीदवार का जीतना तय माना जा रहा है. छठे सदस्य की जीत के लिए अतिरिक्त मत जुटाने होंगे. जानकारों के मुताबिक एक उम्मीदवार की जीत के लिए 22 विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी. एनडीए के पास भाजपा के 78, जदयू के 45 और हम के चार एवं एक निर्दलीय विधायक के वोट हैं. इनमें तीन सीटें भाजपा आसानी से जीत लेगी. जदयू की दो सीटें निकल आयेंगी. इनमें एक सीट पर मुख्यमंत्री का निर्वाचन होगा. दूसरी सीट पर जदयूके ही किसी दिग्गज को भेजा जायेगा.

### विधान परिषद में कुल 75 सीटें

गौरतलब है कि विधान परिषद में कुल 75 सीटें हैं. इसमें विधानसभा सदस्यों द्वारा 27 जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है, विधान परिषद की एक-तिहाई सीटें हर दो साल के बाद रिक्त होती है, जिस पर मतदान कराया जाता है. इसी क्रम में विधान परिषद की 11 सीटों पर निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल छह मई को पूरा हो रहा है. इन सभी सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाना है. विधान परिषद सदस्यों के लिए विधानसभा में ही बूथ का गठन किया जाता है.

### जीतन राम मांझी के बेटे को भी सदस्या की जरूरत

नयी सरकार में हम पार्टी के एक संतोष कुमार सुमन मंत्री बनाये गये हैं. संतोष कुमार पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बेटे हैं. अभी वो विधान परिषद के सदस्य हैं, लेकिन उनका कार्यकाल भी मई में पूरा हो रहा है. लिहाजा मंत्रिमंडल में बने रहने के लिए उन्हें विधान परिषद या विधानसभा की सदस्यता ग्रहण करनी होगी. विधान परिषद के लिए हम को अपने चार विधायकों के अलावा भाजपा और जदयू के बाकी वोटों की दरकार होगी. इसके बावजूद जीत के लिए अतिरिक्त मतों की जरूरत होगी.

### हम को साथ की जरूरत, इंडिया गठबंधन का जानिए गणित..

इधर, इंडिया गठबंधन में राजद अपनी 79 विधायकों के दम पर तीन सीटें निश्चित रूप से जीतने में सफल होगा. बाकी के दो सीटों के लिए कांग्रेस के 19 और राजद के बाकी मत आधार वोट होंगे. जीत के लिए वामदलों के 16 विधायकों का समर्थन जरूरी होगा. खाली हो रही सीटों में एक कांग्रेस की भी सीट है. पार्टी के विधान पार्षद प्रेमचंद्र गुप्ता का कार्यकाल मई में समाप्त हो रहा है.कांग्रेस को अपनी सीटें बरकरार रख पाने के लिए राजद के तीन मतों की जरूरत होगी.

## संक्षिप्त समाचार

### प्रखंड स्तरीय विज्ञान मेला में घनश्यामचक अव्वल

**भागलपुर/सन्हौला, एजेंसी।** प्रखंड परिसर के सिल्क प्रशिक्षण भवन में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अजेयेश्वर कुमार पाण्डेय की अध्यक्षता मे प्रखंड स्तरीय विज्ञान मेला का आयोजन किया गया। इसमें सन्हौला प्रखंड क्षेत्र के कुल 13 स्कूल के बच्चों के टीम से प्रोजेक्ट बनाकर भाग लिया। इसमें मध्य विद्यालय घनश्यामचक के बच्चों ने पर्यावरण पर आधारित प्रोजेक्ट को प्रथम स्थान मिला, द्वितीय स्थान पर मध्य विद्यालय धुंआवे रहा। तृतीय स्थान पर मध्य विद्यालय नारायण बाटी रहा। कार्यक्रम में निर्णायक की भूमिका में डॉ. सुनील कुमार शुक्ल, पूर्व बीआरपी सुनील कुमार सिंह, बीआरपी अवधेश सिंह, बीआरसी के पवन कुमार, बीपीएम हिमांशु कुमार, नारायण बाटी विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक कृष्ण मुरारी सिंह, उर्दू विद्यालय बखड्डा सहायक शिक्षक के अरविंद कुमार सहित कई शिक्षक मौजूद थे। वही विज्ञान प्रदर्शनी मेला में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अजेयेश्वर पांडे ने बताया कि तीनों टीम के प्रतिभागी बच्चों का चयन कर जिलास्तर पर भेजा जाएगा, जो जिला मे आयोजित जिला स्तरीय विज्ञान मेला मे अपना प्रदर्शन कर सके।

### एनटीपीसी संत जोसेफ स्कूल के दो खिलाड़ी का प्रदर्शन बेहतर

**भागलपुर/कहलगांव, एजेंसी।** युवा एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार की ओर से तमिलनाडु के कोयंबटूर में 28-30 जनवरी तक आयोजित 6वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सेंट जोसफ स्कूल एनटीपीसी विद्यालय के दो खिलाड़ियों ने थांग-टा में बेहतर प्रदर्शन किया। इसमें हर्षित कुमार( फुमाबा अमा-60 किलो) में चौथी रैंक व तेजस्विनी सिंह( फुमाबा अनिशुबा-52 किलो ) में आठवी रैंक प्राप्त की। प्रतियोगिता में पूरे बिहार से छह खिलाड़ियों का चयन किया गया था। इसमें भागलपुर जिले से एनटीपीसी संत जोसेफ स्कूल के दो खिलाड़ी थे। विद्यालय परिवार और बिहार थांग टा संघ ने बधाई व शुभकामनाएं दी।

### शाहकुंड-अंडा व फल नहीं मिलने पर छात्रों का हंगामा

**भागलपुर/शाहकुंड, एजेंसी।** प्रखंड के मिडिल स्कूल गोरगामा में स्कूली बच्चों ने भोजन में अंडा व फल नहीं मिलने पर स्कूल परिसर में हंगामा किया। साथ ही स्कूल के प्रभारी पर गड़बड़ी का आरोप लगाया। बुधवार को मिडिल स्कूल गोरगामा में मीनू में अंडा या फल था। लेकिन स्कूल में बच्चों को अंडा नही दिया जा रहा था। इसके कारण स्कूल की कुछ छात्रों ने अंडा की मांग की और कहा की आसपास के सभी स्कूलों में ऐसा हो रहा है। छात्रों के विरोध से स्कूल में हलचल मच गया। बता दे कि विभाग ने एमडीएम में 27 जनवरी से 17 फरवरी तक अंडा व फल देने का विशेष निर्देश जारी किया है। इसके बाबजूद ऐसा नहीं किया गया है। इधर एचएम अरबिंद कुमार गुप्ता ने बताया कि छात्रों का आरोप गलत है। विभागीय निर्देश के आलोक में नियमित बच्चों को मीनू के अनुरूप ही व्यवस्थाएं की गई है।

### होटल संचालक को पीआर बॉन्ड पर छोड़ा

**मुजफ्फरपुर/मोतीपुर, एजेंसी।** बरूराज थाना क्षेत्र के बखरी के पूर्व उपमुखिया अशोक कुमार राय की गोली मारकर हत्या के मामले में अब तक परिवार की ओर से शिकायत नहीं की गयी है। थानाध्यक्ष ने बताया कि हिरासत में लिए गये होटल संचालक को पूछताछ के बाद कोई ठोस सबूत नहीं मिलने पर पीआर बॉन्ड पर रिहा कर दिया गया, फिलहाल पूर्व उपमुखिया के मोबाइल के नंबर की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि पूर्व उपमुखिया के मोबाइल पर एक नंबर से कई बार घंटों तक बात होना सामने आया है। थानाध्यक्ष संजीव कुमार दुबे ने बताया कि पीड़ित परिवार को लिखित शिकायत देने के लिए बार-बार कहा जा चुका है। बावजूद परिजन आवेदन नहीं दे रहे हैं, जिस कारण जांच आगे नहीं बढ़ पा रही है।

## कोर्ट में आत्मसमर्पण के बाद हत्या के आरोपित को जेल

**मुजफ्फरपुर, एजेंसी।** कांटी थाना के सरमसपुर में राजा कुमार चौधरी की हत्या के आरोपी अर्जुन साह ने बुधवार को विशेष एससी-एसटी कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। मृतक राजा कुमार चौधरी के भाई विकास कुमार चौधरी ने बीते साल 27 नवंबर को कांटी थाना में अर्जुन साह सहित पांच पर हत्या की एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें आरोपितों पर हत्या कर शव को बागीचे में पेड़ से लटका देने का आरोप है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद अर्जुन की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही थी। इसी दबाव में वह बुधवार को न्यायालय में अपने वकील के माध्यम से हाजिर हो गया। विकास कुमार चौधरी ने पुलिस को बताया था कि ठेकेदर अर्जुन साह के साथ वह और उसका भाई राजा कुमार चौधरी गाजियाबाद में मजदूरी करते थे। अर्जुन के यहां 54 हजार रुपये बकाया हो गया था। रुपये नहीं मिलने पर विकास और राजा ने दूसरे ठेकेदार के साथ गाजियाबाद जाने की बात तय कर ली थी। मजदूरी के लिए जब दोनों भाई जाने लगे तो रास्ते में घेरकर आरोपित अर्जुन साह ने मारपीट की।

**नगर परिषद में अतिक्रमण हटाओ अभियान चला, लोगों को चेताया गया**

## एनएच-83 के अतिक्रमण कर लगाए अवैध दुकानों पर चला बुलडोजर

**जहानाबाद, एजेंसी।** जहानाबाद के प्राचीन देवी मंदिर के पास एनएच-83 के अतिक्रमण कर लगाए गए अवैध दुकानों पर नगर परिषद के अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए रोड को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इस दौरान मौजूद लोगों ने बताया कि दुकानों के लिए पहले की स्थान निर्धारित कर दी गई है। बावजूद इसके दुकानदारों द्वारा सड़क अतिक्रमण कर दुकान लगा दिया है, जिसके कारण लोगों को आने-जाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। सड़क दुर्घटना की भी संभावना बनी रहती है। नगर परिषद के सिटी मैनेजर कुमार गौरव ने बताया कि सड़क पर दुकान लगाने वाले दुकानदारों को बार-बार चेतावनी दी जा रही है कि आप लोग सड़क पर किसी भी हाल में दुकान नहीं लगे जिस जगह आप लोगों को सब्जी मंडी लगाने का निर्धारण किया गया है। उसी जगह पर अपना दुकान लगाई लेकिन सब्जी बेचने वाले दुकानदार सड़क के किनारे दुकान लगा देते हैं, जिसे जाम की समस्या बन जाती है और लोगों को आने-जाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसके कारण कभी भी बड़ा हादसा भी हो सकता है। इसी को लेकर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया। कई लोगों को दुकान हटाया गया और कई लोगों को जुर्माना भी लगाया गया है। उन्होंने कहा कि शहर में लगातार या अभियान चलता रहेगा जो लोग भी सड़क के किनारे दुकान लगाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई से फुटपाथ की दुकानदारों में हड़कंप बच गया।

# शाहकुंड प्रखंड मुख्यालय की बैठक में उठे मुद्दे

**भागलपुर/शाहकुंड, एजेंसी।** बुधवार को शाहकुंड प्रखंड मुख्यालय के शिल्पी भवन में पंचायत समिति सदस्यों की बैठक प्रमुख अंजना कुमारी की अध्यक्षता में हुई। प्रखंड के एक भी मुखिया शामिल नहीं होने से सर्वसम्मति से बैठक का मुखिया बहिष्कार कर विरोध कर दिया। मुखिया संघ के अध्यक्ष विश्वनाथ महतो व उपाध्यक्ष सह जिलासचिव उत्तम कुमार सिंह ने आरोप लगाया कि पूर्व में हुए बैठक में लिए गए निर्णय व प्रस्ताव पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। बैठक में सिर्फ खानापूर्ति की जाती है। साथ ही सदन की गरिमा का कोई ख्याल नहीं रखा जाता है। उन्होंने कहा कि जब तक बैठक में डीडीसी या कोई भी वरीय पदाधिकारी शामिल नहीं होंगे तब तक हमलोग बैठक में भाग नहीं लेंगे। इधर लंबे इंतजार के बाद मुखिया के अनुपस्थिति में ही सदन की कार्रवाई पंसस के साथ प्रारंभ हुई। इसमें वासुदेवपुर पंसस अशोक यादव ने राशन कार्ड बनाने में वसूली के गंभीर आरोप लगाए। मामले की गंभीरता को देखते हुए अनुपस्थित एमओ के विरुद्ध प्रस्ताव लेने का निर्णय लिया। कसवा खेरही पंसस चंदा कुमारी व संजय मोदी ने आंगनबाड़ी केन्द्रों पर बाहली, प्रमाणपत्र बनाने में सेविकाओं की वसूली, केंद्र पर पेयजल की समस्या, निजी मकानों में चल रहे केंद्र की समस्याओं से अवगत कराया। सीडीपीओ कुमारी हेमा ने समाधान का भरोसा दिया। स्वास्थ्य की बदहाली को लेकर कई सदस्यों ने तीखे प्रहार किए। डॉक्टर, दवा नहीं मिलने की बात कही गई। शाहकुंड सीएचसी में रोगी को कंबल नहीं मिलने, बेड सीट नहीं बदलने समेत कई गंभीर आरोप लगाए गए। पंसस ममता शर्मा ने शिक्षा विभाग में उपस्थिति में फर्जीवाड़ा करने व घटिया एमडीएम देने की बात से सदन को अवगत कराया।

शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि ने एमडीएम में औसतन छह रुपये रूपए प्रति बच्चे के हिसाब से राशि मिलने की जानकारी दी। सदस्यों ने सदन के माध्यम से इसे बढ़ाने की मांग करने का निर्णय लिया। वहीं, नल से जल की व्यापक गड़बड़ी की शिकायत किया। पदाधिकारी ने योजना पीएचईडी को सौंप दिए जाने की जानकारी देते हुए, जल्द निबटारे की बात कही। पैरडोमिनियां पसस ने एक ही जमीन की रसीद अंचल कार्यालय द्वारा दो व्यक्ति के नाम से निर्गत किए जाने का आरोप लगाया। सीओ ने जांच करने की बात कही। बैठक में बीडीओ अभिनव भारती, सीओ निलेश चौरसिया, बीपीआरओ निलेश कुमार, बीसीओ किसलय कृष्ण, बीएओ रामयश मंडल, उपप्रमुख तरन्नुम अनवर, फरहत प्रवीण, निवास साह आदि उपस्थित थे।

## तेजस्वी यादव के कारण ही 4 लाख लोगों को नौकरी मिली; नीतीश के आरोपों पर आरजेडी का पलटवार

**पटना, एजेंसी।** बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद आरजेडी और जेडीयू में सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव समेत आरजेडी नेताओं पर काम का श्रेय लेने का आरोप लगाया। अब आरजेडी ने इस पर पलटवार किया है। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि तेजस्वी यादव के कारण ही बिहार में 4 लाख लोगों को नौकरी मिली। उनका विजन नौकरी और रोजगार था। तेजस्वी यादव के स्वास्थ्य विभाग ने 1.35 लाख नौकरी देने की प्रक्रिया पूरी कर ली थी, जिसे दो महीने में पूरा किया जाए। आरजेडी नेता मनोज झा ने बुधवार को कहा कि पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई लड़ें लेकिन रोजगार और नौकरी को बाधित न करें। महागठबंधन की सरकार बनने से पहले तेजस्वी की शर्त थी कि बिहार में नौकरी एवं रोजगार के संकल्प को पूरा करना है। उन्होंने एक लाख और शिक्षकों की नियुक्ति को 30 से 40 दिनों में तथा गृह विभाग, सहकारिता विभाग सहित अन्य विभागों के लिए चिह्नित रिक्तियों को ससमय भरने की मांग की। उन्होंने कहा कि आशा और ममता के मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में रोक दिया गया जबकि स्वास्थ्य मंत्री के रूप में तेजस्वी यादव ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। उन्होंने केंद्र से आरक्षण के बढ़ाए दायरे को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की भी मांग की। मनोज झा ने दावा किया कि तेजस्वी यादव के संकल्प के अनुसार जो काम 17 सालों में एनडीए की सरकार ने नहीं किया उसे 17 महीने में पूरा किया गया। उन्होंने स्टेडियम निर्माण, अस्पताल भवन निर्माण सहित अन्य कार्यों को भी पूरा करने की मांग की। वहीं, तंज कसा कि सरकारें विकास और गरीबों के चेहरे पर मुस्कान के लिए बनती हैं न कि मंदिर-मस्जिद और गुरुद्वारा निर्माण के लिए।

# जेडीयू-राजद से पूछना चाहिए पार्टी चलाने के लिए कहां से आ रहा पैसा-प्रशांत किशोर

चाणक्यभूमि बेगूसराय।

पटना में बीते दिनों लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव और तेजस्वी यादव से ईडी की टीम ने घंटों पूछताछ की। वहीं, झारखंड में भी सीएम हेमंत सोरेन से भी जमीन घोटाले को लेकर ईडी की टीम ने घंटों पूछताछ की, उसके बाद हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना पड़ गया। इधर, बेगूसराय में जन सुराज की पदयात्रा को लेकर फंडिंग कहां से आ रही है? इस सवाल का जवाब देते हुए जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि जिस दिन से हम पदयात्रा कर रहे हैं पहले दिन से हर प्रखंड में पत्रकार वार्ता में लोग पूछते हैं कि पदयात्रा के लिए पैसा आ कहां से रहा है। ये सही सवाल है। ये पैसा वहां से आ रहा है जहां हमने बीते 10 साल में जिनको राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ाने में मदद की है, कंधा लगाया है। आज इस देश में 5 से ज्यादा ऐसे राज्य में हैं जहां उन लोगों की सरकार है जिन्हें जिताने में, सरकार बनाने में हमने कंधा लगाया है। कई लोगों को ये लगता है कि हमने जिस पार्टी को जिताया है वो पैसा दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पैसा कोई नेता या दल नहीं देता है, लेकिन जिस राज्य में सरकार बनाने में मदद की है, उस राज्य में सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो प्रशांत किशोर को जानते हैं, जिनको हमारी समझ पर भरोसा है, जिनको हमारे प्रयास पर यकीन है, वो लोग मदद करते हैं। उन राज्यों में जहां मैंने 10 साल काम किया, जहां की व्यवस्था को, सरकार को बनाने में हमने कंधा लगाया। उस व्यवस्था से, उन दलों से, उन नेताओं से जुड़े हुए जो लोग हैं वो पैसा दे रहे हैं उसी से ये अभियान चलाया जा रहा है। लालू, नीतीश और तेजस्वी यादव से आप ये सवाल जीवन में कभी नहीं पूछ पाइएगा क्योंकि वे आपको पूछने नहीं देंगे, उनके जिलाध्यक्षों से पूछिए: प्रशांत किशोर प्रशांत किशोर ने कहा कि एक बार ये सवाल जेडीयू और राजद से भी जरूर पूछिएगा। वहीं, फुटेज हमें भी दिखाइएगा जिसमें आप तेजस्वी यादव से पूछ रहे हों कि राजद को राजनीति करने के लिए पैसा कहां से आता है। अपना बर्थ डे चार्टर्ड प्लेन में मनाने में के लिए पैसा कहां से आता है? नीतीश कुमार को धंधेबाजी करने के लिए पैसा कहां से आता है? ये सवाल आपने नीतीश कुमार से पूछा होता तो मुझे बहुत खुशी होती। आपने मुझसे ये सवाल

पूछा, सवाल पूछना आपका हक है और जवाब देना हमारा। लेकिन, ये सवाल सबसे मांगा जाना चाहिए। दूसरे लोग जवाब न भी दें तो भी मैं जवाब दूंगा। पत्रकार होने के नाते आप गिरिराज सिंह से भी ये सवाल पूछिएगा, डॉ तनवीर से भी सवाल पूछिएगा और नीतीश कुमार, लालू यादव और तेजस्वी यादव से भी ये सवाल पूछिए कि राजद और जेडीयू को पैसा दे कौन रहा है, जवाब तो आपको जीवन में नहीं मिलेगा। बिहार में ऐसा कोई नहीं है जो ये कह दे कि वो जन सुराज को पैसा दे रहा है। लालू यादव, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से आप ये सवाल जीवन में कभी नहीं पूछ पाइएगा क्योंकि वे आपको पूछने नहीं देंगे, कम से कम उनके जिला अध्यक्षों से पूछिए कि उनके पास पैसा कहां से आता है।

# उपप्रमुख मझौलिया पर लगा अविश्वास खारिज

सम्बाददाता.(कनकलता)

**बेतिया। गुरुबार के दिन प्रखंड उपप्रमुख नरेश कुमार यादव पर लगा अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया। जानकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी वरुण केतन ने दी।उन्होंने बताया कि सदन में बहस के लिए 20 समिति सदस्यों की आवश्यकता थी।लेकिन सदन में मात्र तीन सदस्य उपस्थित हुए।बीडीसी सदस्य सुक्तामुखी, अरविन्द कुमार और सरिता देवी ही उपस्थित हुए।कोरम के अभाव में अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया।उन्होंने बताया कि अविश्वास प्रस्ताव महनागन्नी समिति सदस्य द्वारा लाया गया था।जिसमें गायत्री देवी, रमावती देवी, प्रतिमा देवी अरविन्द कुमार आदि समिति सदस्य शामिल थे।खारिज होने पर उपप्रमुख के समर्थको ने फूल माला पहनाकर तथा अबीर गुलाल लगाकर स्वागत किया।उपप्रमुख नरेश कुमार यादव ने समर्थकों का आभार व्यक्त किया।उन्होंने सबके साथ मिलकर विकास कार्य करने की बात कही।समाजसेवी मंटू कुशवाहा ने नरेश कुमार को पुनः काबिज होने पर बधाई दी है।**

## पुलिस अधीक्षक सुशांत कुमार सरोज ने थाने का किया निरीक्षण

बगहा

बगहा पुलिस जिला के नये पुलिस अधीक्षक सुशांत कुमार सरोज ने अपने कार्यकाल के दूसरे दिन थाने का निरीक्षण करने पहुंचे और इस दौरान थानाध्यक्ष को कई दिशा निर्देश दिया। हालांकि की थानों की साफ-सफाई देख इन्होंने प्रशंसा की और कहा कि कार्य साफ-सुथरे माहौल में हो। एसपी सुशांत सरोज नेपाल औऱ यूपी सीमा पर स्थित बगहा की भौगोलिक स्थिति का जायजा ले रहे हैं। थाने के निरीक्षण के क्रम में आज वे रामनगर थाना पहुंचे, जहां उनका पुलिसकर्मियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। एसपी ने बताया की फिलहाल वे पूरे क्षेत्र का भौगोलिक जायजा ले रहे हैं। साथ ही थानों का भ्रमण कर उनकी स्थिति देख समझ रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि कुछ पदाधिकारियों के चुनाव के मद्देनजर तबादला हो गया है, और कुछ नए आए भी है। वह हम बाद में देखेंगे कि थानों में लंबित मामलों का निपटारा जल्द और कैसे हो। बतादें की इस दौरान एसपी ने अपराध नियंत्रण को लेकर थानाध्यक्ष को जरूरी दिशा-निर्देश भी दिया है।

## अमिरो और पुंजीपतियों का बजट आम आदमी के लिए कुछ नहीं: माले

चाणक्यभूमि बेतिया।

भाकपा-माले नेता और किसान महासभा ने जिला अध्यक्ष सुनील कुमार राव ने 2024- 25 के लिए प्रस्तुत अंतरीम बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मोदी सरकार ने कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनरेगा और लोक कल्याण के खर्चों में पिछले वर्ष की तुलना में कटौती की है। महंगाई रोकने के लिए ना आम जनता को पेट्रोल- डीजल, गैस की सिलेंडर की कीमतों में राहत मिली और ना ही युवाओं को रोजगार मुहैया कराने पर कोई ठोस कार्ययोजना पेश की गई। महंगाई से पीड़ित महिलाओं को गैस सिलेंडर के दाम में छोटी सी राहत भी नसीब नहीं हुई। मोदी सरकार के पास इस बजट में देश की गृहणियों को देने लिए कुछ भी नहीं है! मनरेगा में पिछले साल का ही बकाया 20 हजार करोड़ है। इस साल उसमें कोई बढ़ोत्तरी नही है ऐसे में पिछले बकाया भरपाई करने

पर इस साल बजट कम हो गया। जबकि गांवों में रोजगार का बड़ा जरिया मनरेगा है। कृषि में खाद सब्सिडी, फसल बीमा योजना, फुड़ सब्सिडी में कटौती की गई है। एम एस पी पर कोई बात नहीं हुई है।इन सारे पैमानों पर देखें तो मोदी सरकार द्वारा पिछले दस वर्षों से पेश किए जा रहे जनविरोधी बजट का ही हिस्सा है। यह बहुत निराशाजनक बजट है। कुल मिलाकर एक बार फिर यह बजट सिर्फ और सिर्फ अमीरों और उद्योगपतियों का बजट है? आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है।

# जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने परीक्षा केन्द्रों का किया औचक निरीक्षण

**• सीटिंग प्लान, फ्रिक्सिंग स्थल, सीसीटीवी कैमरा, वीडियोग्राफी, साफ-सफाई आदि का लिया जायजा।**
**• जिले के कुल-53 परीक्षा केन्द्रों पर दो पालियों में स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त संचालित हो रही है परीक्षा।**

बेतिया।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा आयोजित इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2024 का आयोजन जिला/अनुमंडल मुख्यालय में कुल-53 परीक्षा केन्द्रों पर आज 01 फरवरी से प्रारंभ हो गया है। यह परीक्षा 12 फरवरी तक दो पालियों में संचालित की जायेगी। परीक्षार्थियों की कुल संख्या-41056 है। जिलाधिकारी, श्री दिनेश कुमार राय तथा पुलिस अधीक्षक, बेतिया, श्री अमरकेश डी द्वारा आज परीक्षा केन्द्रों औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान आर0 एल0 एस0 वाई0 कॉलेज, विपिन हाईस्कूल, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, धांगड़ टोली सहित अन्य विद्यालयों का निरीक्षण किया गया तथा प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, केन्द्राधीक्षक एवं वीक्षक को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया। इस क्रम में जिलाधिकारी द्वारा सीटिंग प्लान, फ्रिक्सिंग स्थल, सीसीटीवी कैमरा, वीडियोग्राफी, साफ-सफाई, अन्य मूलभूत सुविधाओं आदि का जायजा लिया गया। सभी परीक्षा केन्द्रों पर सभी व्यवस्थाएं दुरूस्त पायी गयी। परीक्षा का संचालन स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त पाया गया। निरीक्षण के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा परीक्षा कार्य में संलग्न सभी केन्द्राधीक्षकों, दंडाधिकारियों, उड़न दस्ता दल के दंडाधिकारियों, पुलिस बल के जवानों आदि को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों का अशरक्षः अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि हर हाल में शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त परीक्षा का संचालन किया जाय। कदाचार में शामिल छात्र-छात्राओं सहित अन्य व्यक्तियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाय। उनके विरूद्ध नियमानुकूल कार्रवाई की जाय। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक, बेतिया, श्री अमरकेश डी, एसडीएम, बेतिया सदर, श्री विनोद कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बेतिया सदर, श्री महताब आलम, जिला शिक्षा पदाधिकारी, श्री रजनीकांत प्रवीण, विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, श्री सुजीत कुमार सहित अन्य प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी उपस्थित थे।

## सरेह मे अज्ञात शव बरामद पुलिस जाँच मे जुटी

चाणक्यभूमि बेतिया।

गुरुवार को लौरिया के रमना सरेह मे एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला । युवक की उम्र 25 वर्ष के आसपास की लगती है । घास काटने गए महिलाओ ने उक्त शव को पेड़ से लटका देखा जिसके बाद लोगों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई । पुलिस ने मौके पर पहुँच कर शव को नीचे उतारा । पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए बेतिया भेज दिया है । पुलिस शव के शिनाख्त मे लागि हुई है । प्रशासन द्वारा बताया गया की प्रथम दृष्टि मे मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है । शव के शिनाख्त के बाद ही मामले की सच्चाई का पता चलेगा ।

## बालू की तस्करी जोरों पर - खनन वीभाग क्यू है चुप

चाणक्यभूमि बेतिया।

बेतिया मे इन दिनों सफेद बालू का अवैध व्यापार जोरों पर है परंतु इसपर खनन वीभाग के अधिकारी मौन है । हालांकि दिखावे के लिए अधिकारी कभी इक्का दुक्का कारवाई करते है परंतु जिस तरह से अवैध बालू का व्यापार खुले आम बेरोकटोक चालू है इससे साफ प्रतीत हो रहा है की कही ना कहीं अधिकारियों की मिलीभगत है क्यूंकी बिना इनके मिलीभगत के इस तरह खुलेआम व्यापार संभव नहीं है । अगर देखा जाए तो प्रतिदिन बड़ी मात्र मे ट्रैक्टर के माध्यम से जिले के विभिन्न क्षेत्रों से अवैध बालू तस्करों द्वारा लाया जाता है । जानकारी के अनुसार इसको रोकने की जबाबदेही खनन के साथ ही पुलिस की भी रहती है परंतु ना जाने वो कौन सी वजह है की कोई भी इन अवैध व्यापारियों पर कारवाई नहीं करना चाहता ।

## मझौलिया के आइसक्रीम फैक्ट्री में लाखों की चोरी

**खिड़की के सहारे अंदर घुसे चोरों ने लगभग तीन लाख रुपये मूल्य की सामग्री चोरी**
**जिसके बाद सूचना पर पहुंची मझौलिया पुलिस ने किया घटनास्थल का निरीक्षण**

बेतिया संबाददाता(कनकलता)

**बेतिया।**बुधवार की देर रात वार्ड नं.3 स्थित चैंपियन आइस क्रीम फैक्ट्री मझौलिया में अज्ञात अपराधकर्मियों ने खिड़की से अंदर घुसकर फैक्ट्री की कीमती सामग्रियों की चोरी कर ली।फैक्ट्री मैनेजर प्रमोद साह की सूचना पर एसआई हैदर अली ने घटना स्थल का निरीक्षण किया।तत्पश्चात एफआईआर दर्ज कर पुलिस तहकीकात में जुट गयी है। एसआई हैदर अली ने बताया की चोरी गयी सामग्रियों में जनरेटर, तांबे का पाईप समेत अन्य कीमती उपस्कर शामिल है। पीड़ित फैक्ट्री मालिक प्रमोद साह ने बताया कि अपराधी मेन गेट पर बांस का बल्ला लगाकर आवागमन अवरुद्ध कर दिया था।ताकि घर मे सोये लोग बाहर नही निकल सके।उन्होंने स्थानीय प्रशासन को घटना की सूचना दी।सूचना पर पहुंची मझौलिया थाना में पदस्थापित ए एस आई हैदर अली ने मामले की जांच पड़ताल शुरु कर दी। पंचायत के मुखिया सत्यप्रकाश तथा बीडीसी प्रतिनिधि सुरेंद्र साह ने घटनास्थल का निरीक्षण कर पुलिस प्रशासन से रात्रि गस्ती तेज करने की मांग की है।उल्लेखनीय है कि बिगत 08 जनवरी को थाना के सामने पंकज किराना दुकान में सेंधमारी कर लाखो रुपये मूल्य की सामग्री की चोरी कर ली गई थी।मामले में पुलिस को अबतक उक्त मामले में कोई सफलता नही मिली।महज 23 दिनों के अंदर दूसरी बड़ी चोरी की घटना हो गयी।चोरी की बढ़ती घटना से व्यवसायियों में दहशत है।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक, सम्पादक अजीत कुमार सिन्हा उर्फ अजीत कुमार द्वारा शिखा प्रिंटिंग प्रेस वास्ते अनिशा डिजिटल प्रिंटर्स द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित ।
किसी भी वाद-विवाद का निपटारा न्यायिक क्षेत्र बेतिया में होगा । सम्पादकिय कार्यालय : नया बाजार, बेतिया, प0 चम्पारण-845438, कार्यकारी सम्पादक : मनिष कुमार, मो0-9472494714